मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- मोदी की मैट्रो सवारी जनता पर पड़ी भारी
- नेताओं व प्रशासन को कुछ तो शर्म आई — 3

- ऐतिहासिक दुकान को बंद कराकर ही मानी नौकरशाही — 4

- कलबुर्गी की हत्या तार्किकता का गला घोंटने का प्रयास
- दूसरो को नहसीत, खुद मियां फजीहत — 5

- वैश्वीकरण दौर में आरक्षण , गुजरात जला, हरियाणा में भी चिंगारी — 8

वर्ष 28 अंक 21 फरीदाबाद, बुधवार, 16-30 सितम्बर 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

ग्यारह मज़दूरों की हत्या जिसके सिर वह संतोष यादव बनी डिप्टी स्पीकर

दिनांक 4 सितम्बर को भाजपा विधायक दल ने अटेली से विधायक निर्वाचित संतोष यादव को विधान सभा का डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) चुन कर यह सिद्ध कर दिया कि उनके गिरोह में ऐसे ही शातिर लोगों की जरूरत है। लगता है इस पद के लिये उनके पास संतोष यादव से बड़ा जनता का अपराधी कोई और नहीं रहा होगा।

मज़दूर मोर्चा, नारनौल ब्यूरो

विदित है कि 7 अगस्त को नारनौल के निकट गांव धोलेड़ा में एक क्रैशर की दीवार गिरने व उसके नीचे दब कर कुल 11 मज़दूरों की मृत्यु हो गयी थी। इनमें से 4 तो एक ही परिवार के थे। मौका-मुआयना करने के बाद 'मज़दूर मोर्चा' के विशेष संवाददाता ने बताया कि विधायक संतोष यादव का एनओसी के रास्ते मोटी कमाई का धंधा रहा है-स्टोन क्रैशर बनाकर बेचने का। अब तक वह अपने इसी क्षेत्र में 5 स्टोन क्रैशर बेच चुकी हैं।

दरअसल स्टोन क्रैशर का बनाना कोई कठिन अथवा बड़ा तकनीकी काम नहीं है। इसके बनाने वाले कारिगर एवं मशीनरी आदि सब कुछ बाज़ार में उपलब्ध हैं; करीब एक करोड़ से डेढ करोड़ खर्च करके कोई भी इसको लगा सकता है। परन्तु जो चीज़ खुले बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, वह है एनओसी यानी सरकार द्वारा जारी किया जानेवाला अनापत्ति प्रमाणपत्र। भाजपा की खट्टर सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों की भांति इसे अपने विधायकों व अन्य खास लग्गुओं-भग्गुओं के लिये ही रखा हुआ है। इसी एनओसी के मिलने से एक-डेढ करोड़ की लागत वाला स्टोन क्रैशर 4-5 करोड़ तक का हो जाता है। यह व्यापार भी ठीक वैसा ही है जैसा ज़मीन का सीएलयू बदलवाने का। यानी एक करोड़ की ज़मीन सीएलयू के बाद 5 से 10 करोड़ तक की हो जाती है।

संतोष यादव	मनोहर लाल खट्टर
	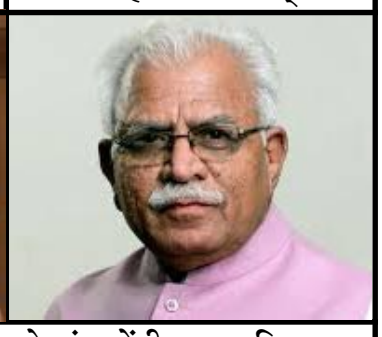

डिप्टी स्पीकर : शातिरों को संभालेंगी महाशातिर

सर्वविदित है कि राजनेता इस तरह के घोटाले कभी अपने खुद के नाम से नहीं करते। इसके लिये वे सदैव अपने यारों-प्यारों एवं रिश्तेदारों का इस्तेमाल करते हैं। 11 मज़दूरों का हत्या स्थल भी संतोष यादव ने अपने नाम की बजाय अपने भाई अनिल के सालों रतन तथा सोहनपाल व नारनौल के एक होटल व्यवसायी लाला चुन्नी के नाम से खड़ा किया था। चुन्नी सेठ की तारीफ़ यह है कि वह विशुद्ध व्यापारी होने के नाते बिना किसी दलीय भेदभाव के सभी राजनेताओं के साथ लेन-देन रखते हैं। इनके काले धन को ठीक से सम्भालना व निवेष करना चुन्नी सेठ का ही दायित्व रहता है।

संतोष यादव के पहले चार क्रैशर ठीक-ठाक बनकर बिक गये थे। प्रत्येक में 4-5 करोड़ तक का मुनाफ़ा कमा लिया गया था। लेकिन पांचवां क्रैशर इस गिरोह पर भारी पड़ गया। मौके पर गयी 'मज़दूर मोर्चा' की टीम ने पाया कि गिरने वाली दीवार बहुत जल्दबाज़ी में तथा निर्माण के सामान्य नियमों का उल्लंघन करके बनाई गयी थी। रैंप के लिये बनने वाली 20 फ़ीट ऊंची व 100 फ़ीट लम्बी दीवार का आसार 8 फ़ीट लिया जाता है। इसको धीरे-धीरे घटाते हुए यानी ज्यों-ज्यों दीवार ऊंची उठती जायेगी, आसार 7 फ़ीट, 6 फ़ीट, 5 फ़ीट और अन्त में ढाई फुट का रखा जाता है।

चिणाई का यह काम बहुत धीरे-धीरे करीब 4 से 6 माह में पूरा किया जाता है ताकि दीवार सूख कर मजबूत हो सके। इस तरह की दो दीवारों के बीच मिट्टी भर कर रैम्प तैयार किया जाता है। मौजूदा मामले में लागत का पैसा बचाने व जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में न तो दीवार के आसार एवं चौड़ाई का ध्यान रखा गया और न ही इसे सूख कर मजबूत होने का अवसर दिया गया। इस प्रकार करोड़ से डेढ करोड़ में तैयार होने वाले इस क्रैशर की लागत भी 60-70 लाख तक ही आई यानी लागत में भारी बचत।

6 माह की बजाय 20 दिन में तैयार की गयी इस गीली दीवार के साथ जब मिट्टी भराई का काम शुरू किया गया तो रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। इससे दीवार में तरेड़ें साफ़ नज़र आने लगी। कार्यरत मज़दूरों ने मालिकान को मौके पर बुला कर इन्हें दिखा भी दिया था। लेकिन जल्द मुनाफ़े की हवस में अंधे मालिकान ने इस दीवार को तोड़ कर दोबारा ठीक से बनाने की बजाय इसी दीवार की मजबूती बढ़ाने के लिये इसके साथ एक पिलर बनवा दिया। इसके बावजूद न तो मिट्टी भराई का काम रोका गया और न ही दीवार के दूसरी ओर फ़र्श का। परिणामस्वरूप गीली दीवार व गीला पिलर मिट्टी भराई का दबाव न झेल पाये और दूसरी ओर काम कर रहे मज़दूरों पर गिर गये। परिणामस्वरूप 11 मज़दूर मौके पर ही दब कर मर गये तथा 8 मज़दूर गंभीर रूप से घायल हो गये।

कानून का पेटा भरने के लिये पुलिस ने किसी मुकेश पुत्र मांगे की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए के तहत रतन, सोहन पाल व दो मुनीमों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली थी। लेकिन मीडिया एवं स्थानीय जनता के दबाव में पुलिस को जुर्म की धारा को 304 ए से बदल कर 304 करनी पड़ी। दूसरे शब्दों में 'दुर्घटना से मौत' के बजाय अब यह 'गैर इरादतन हत्या' का मामला है।

मौके पर गई 'मज़दूर मोर्चा' टीम को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि जिस भूखंड पर यह क्रैशर बनाया जा रहा था वह भी इन बनाने वालों की नहीं थी। उक्त ज़मीन दो भाईयों की मिलकियत है। संतोष यादव ने राजस्व रिकार्ड में हेराफ़ेरी करा कर उक्त ज़मीन एक भाई के नाम करा कर उससे अपने आदमियों के नाम खरीद ली थी। इस मामले की शिकायत जब उपायुक्त को की गयी तो उन्होंने इस घोटाले पर कोई एक्शन लेने की बजाय तुरंत संतोष यादव को सूचित करके रजिस्ट्री रूकवाने की सलाह दी तथा बिना किसी कसूर के तहसीलदार का तबादला आदेश ज़ारी करा दिया।

शातिरों की है जरूरत

डिप्टी स्पीकर पद की दौड़ में अनेकों विधायकों की तरह बल्लबगढ और पृथला के विधायक मूल चंद और टेकचन्द भी थे। परन्तु भाजपा की नज़रों में ये अभी इतने शातिर नहीं हो पाये हैं जितने शातिर व्यक्तित्व की इस पद के लिये जरूरत समझी गयी थी। भविष्य में कभी इस तरह के किसी पद को पाने के लिये इन्हें संतोष यादव से बढ कर अपनी शातिरता सिद्ध करनी पड़ेगी तभी इस भाजपाई राजनीति में आगे बढ पायेंगे।

ख़बर दार

भ्रष्टाचार किस चिडिया का नाम है जी!

इस बार का काल्पनिक साक्षात्कार दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा जनाब केजरीवाल के साथ। अन्ना हज़ारे को लोकपाल का घोड़ा बना कर सवारी गांठने वाले केजरीवाल ने लोकपाल शब्द का उच्चारण ही बन्द कर रखा है। भ्रष्टाचार को उन्होंने होर्डिंग्स और विज्ञापनबाज़ी तक सीमित कर छोड़ा है। मज़दूर मोर्चा ने उनसे इस ह्रदय परिवर्तन के पीछे की कहानी जानने का प्रयास किया।

म.मो.-केजरीवाल जी क्या आपने आजकल नयी डिक्शनरी छपवा ली है, जिसमें लोकपाल शब्द को ही उड़ा दिया गया है?

केजरीवाल-अरे भई मैं ही अकेला नहीं हूं जो इस शब्द का उच्चारण करने से परहेज कर रहा है। स्वयं अन्ना भी कभी-कभार भूले-भटके ही इसका ज़िक्र करने का दु:साहस कर पाते हैं। किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, स्वामी अग्निवेश, रामदेव,श्री श्री रविशंकर और यहां तक कि मेरा अपना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपनी-अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को निकाल चुके हैं।

म.मो.-समझ में नहीं आता कि आपने लोकपाल के मुद्दे को तिलांजलि क्यों दे रखी है? जनता को आपने इसी जाल से तो फ़ांसा था।

केजरी-जब जनता एक बार फ़स ही गयी तो अब इस जाल की क्या जरूरत? देखते नहीं कि भाजपा कांग्रेस समेत कोई भी राजनीतिक दल आज के दिन यह मांग नहीं रख रहा। सही बात तो यह है कि इस जाल में खुद हमारे अपने फ़ंसने का भी खतरा है। ये योगेन्द्र यादव और प्रशान्त भूषण जो आजकल छुट्टे घूम रहे हैं, हमारे पुराने राज़दार रहे हैं। और कोई हमें फ़ंसाये या न फ़ंसाये ये लोग जरूर हमें इस जाल में फ़ंसा देंगे।

म.मो.-पर क्या यह जनता के साथ विश्वासघात जैसा नहीं है? आप का कार्यकर्ता तो यह भी नहीं समझ पा रहा कि पार्टी के आन्तरिक लोकपाल रामदास की छुट्टी क्यों कर दी गयी?

केजरी-और ज़्यादा न ही कहलवाओ तो ठीक है। रामदास को आन्तरिक लोकपाल इसलिये बनाया था कि वह मौका पड़ने पर हमें चरित्र प्रमाणपत्र देता रहे। लेकिन उसका दोगलापन तो देखो। वह तो वास्तव में ही बेईमानी पकड़ने लगा। हमारी बिल्ली हमीं से म्याऊं। ऐसे में रामदास की छुट्टी करने के अलावा और चारा ही क्या था? भला हम अपने विश्वस्त साथियों को सत्ता की मलाई खाने से कैसे रोक सकते हैं?

म.मो.-कोई अपना आदमी लोकपाल बनाकर योगेन्द्र यादव और प्रशान्त भूषण जैसे उत्पातियों को 'ठंडा' क्यों नहीं कर देते?

केजरी-कोशिश तो यही थी और हमने एक नाम छांट भी लिया था पर उपराज्यपाल और हाईकोर्ट ने हमारी चलने नहीं दी। अब बड़ा पैनल बना है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है।

म.मो.-मानना पड़ेगा आपको। पूरे साक्षात्कार के दौरान आपने अपने मुंह से एक बार भी लोकपाल शब्द का उच्चारण भूले से भी नहीं किया। हद से हद आन्तरिक लोकपाल तक ही सीमित रहे।

केजरी-भई आन्तरिक लोकपाल तो अपना ही खिलोना है, उससे तो हम खेल ही सकते हैं। और यह जो दूसरा असल में भ्रष्टाचार पकड़ने वाला है उसके बारे में तो हमने पार्टी मीटिंग में तय कर लिया है कि कोई भी उसका नाम न ले।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 15 सितम्बर को एमसीआई (मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इंडिया) ने गत 6 वर्षों से बन रहे मेडिकल कॉलेज को आखिरकार स्वीकृति प्रदान कर ही दी। नियमानुसार एमसीआई ने इस कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद अब इसे एमबीबीएस छात्रों को पढाने लायक समझ कर केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय को अपनी सिफ़ारिश भेज दी है। जिसके आधार पर मन्त्रालय इसी सत्र से एमबीबीएस छात्रों की पढाई का आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार 100 छात्र एमबीबीएस के कोर्स में इसी माह दाखिला ले सकेंगे।

नियमानुसार 15 सीटें केन्द्र सरकार के खाते में, 42 सीटें ईएसआई कार्डधारकों के बच्चों के लिये तथा शेष 43 सीटें हरियाणा सरकार द्वारा भरी जानी हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हरियाणा सरकार के खाते में 70 से 80 सीटें या इससे भी अधिक जाने की संभावना दिखती है।

सर्वविदित है कि यह मेडिकल कॉलेज 2012 के सत्र से सुरू हो जाना चाहिये था, परन्तु निकम्मे व नालायक राजनेताओं व भ्रष्ट अधिकारियों की हरामखोरी के चलते इसके कभी भी न चल पाने के हालात बन गये थे। लेकिन स्थानीय मज़दूरों व नागरिकों के प्रयासों से ईएसआई निगम में डीजी के पद पर जून 2015 में दीपक कुमार की नियुक्ति हो गयी तथा उनके सद्प्रयासों से कॉलेज को चलाने के काम ने गति पकड़ी और अब यह हर तरह से तैयार है।

विदित है कि इस कॉलेज के साथ 500 बेड का अति आधुनिक अस्पताल है जिसे बहुत तेज़ी से विभिन्न प्रकार के उपकरणों से लैस करने का काम भी पूरी तेज़ी के साथ ज़ारी है।